



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 अप्रैल, 2006 / 17 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 7 अप्रैल, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न. बिल-1-26/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2006 (2006 का

विधेयक संख्यांक 13) हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

१६।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) विधेयक, 2006

(विधान सभा में यथापारित रूप में)

शिमला नगर की सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर, लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में पैदल चलने वालों को क्षोभ और क्षति के निवारण हेतु यानीय यातायात को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार शिमला नगर की नगरपालिक सीमाओं तक है ।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “अधिनियम” से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है;

(ख) “सहायक आयुक्त” से राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 9 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त अभिप्रेत है;

(ग) “उपायुक्त” से जिले के सामान्य प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) “मण्डलायुक्त” से राजस्व मण्डल शिमला का मण्डलायुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) “फीस” से इस अधिनियम के अधीन पास की प्रोसेसिंग करने तथा उसे प्रदान करने हेतु प्रभार्य रकम अभिप्रेत है;

- (च) “निधि” से इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्थापित शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा उन पर पैदल चलने वालों की सुख-सुविधा निधि अभिप्रेत है;
- (छ) विभागाध्यक्ष से, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डेलीगेशन ऑफ फाइनैन्शल पावरज रूलज, 1978) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति है, जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे;
- (ज) “कार्यालय का प्रधान” से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 (डेलीगेशन ऑफ फाइनैन्शल पावरज रूलज, 1978) के नियम 14 के अधीन इस रूप में घोषित राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति है, जिसे सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालय का प्रधान विनिर्दिष्ट करे;
- (झ) उच्च पदस्थ से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
- (i) भारत का राष्ट्रपति;
 - (ii) भारत का उप-राष्ट्रपति;
 - (iii) भारत का प्रधानमन्त्री;
 - (iv) भारत का मुख्य न्यायाधीश;
 - (v) हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल;
 - (vi) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
 - (vii) लोक सभा का अध्यक्ष;
 - (viii) हिमाचल प्रदेश का मुख्यमन्त्री;
 - (ix) हिमाचल प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष;
 - (x) हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश;
 - (xi) हिमाचल प्रदेश के मन्त्री;
 - (xii) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
 - (xiii) हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री; और
 - (xiv) थलसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष;
- (ञ) “पास” से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क या दोनों पर वाहन चलाने के लिए जारी किया गया पास अभिप्रेत है;
- (ट) विशिष्ट व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—
- (i) हिमाचल प्रदेश का महाधिवक्ता;
 - (ii) संसद और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य;
 - (iii) राज्य सरकार का मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव;
 - (iv) थलसेना प्रशिक्षण कर्मीण्ड का मुख्य जनरल आफिसर कर्मीण्डिंग;

- (v) सुपर टाईम वेतनमान या इससे अधिक वेतनमान में, शिमला में तैनात, केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी;
 - (vi) सुपर टाईम वेतनमान में, शिमला में तैनात, राज्य के न्यायिक अधिकारी;
 - (vii) मेजर-जनरल या इससे ऊपर की पंक्ति के शिमला में तैनात सैन्य अधिकारी;
 - (viii) नगर निगम शिमला का महापौर और पार्षद; और
 - (ix) सुपरटाईम वेतनमान और इससे अधिक के वेतनमान में, हिमाचल प्रदेश के बोर्डों, निगमों या कानूनी (वैधानिक) आयोगों के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य।
- (ठ) “लोक-उपयोगी यान” से आवश्यक सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित वाहन अभिप्रेत हैं:-
- (i) आग बुझाने वाले यान;
 - (ii) रोगी वाहन और मृतक वाहन (डैड बॉडी वैन);
 - (iii) डाक वाहन;
 - (iv) संचार एवं अन्य लोक सेवाओं के रख-रखाव के लिए अभिनियोजित यान या गृह विभाग द्वारा अनुमोदित लोक परिवहन यान;
 - (v) नगर निगम शिमला द्वारा स्वच्छता, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सेवाओं के रख-रखाव के लिए अभिनियोजित यान तथा जिसमें नगर निगम अधिकारियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण और उक्त कर्तव्यों के संधारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी यान भी सम्मिलित हैं; और
 - (vi) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड), सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम शिमला आदि के भारी वाहन जो किन्हीं सन्निर्माण या अनुस्क्षण क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अभिनियोजित किए गए हों;
 - (vii) जिला प्रशासन, शिमला तथा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा उच्च पदस्थों के साथ प्रोटोकॉल डियूटी के लिए अपेक्षित सरकारी यान।
- (ड) “प्रतिबन्धित सड़क” से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट सड़क अभिप्रेत है;
 - (ढ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (ण) “सील्ड सड़क” से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सड़क अभिप्रेत है;
 - (त) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
 - (थ) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
 - (द) “सुपरटाईम वेतनमान” से 18400-22400 रुपये का वेतनमान अभिप्रेत है।

(2) उन समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः हैं।

सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यानों के प्रयोग पर निर्बन्धन।

3. (1) अनुसूची -1 में विनिर्दिष्ट समस्त सील्ड सड़कों, उच्च पदस्थों और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा यानों के सिवाए, समस्त मोटर यातायात के लिए सील्ड होंगी और कोई भी व्यक्ति अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सड़कों पर, इस अधिनियम के अधीन, पास प्राप्त किए बिना कोई यान नहीं चलाएगा:

परन्तु यह कि,—

- (i) पास, ऐसे लोक-उपयोगी यान के लिए, सचिव (गृह) द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकेंगे, जैसा लोकहित में आवश्यक समझा जाए;
- (ii) प्रमुख व्यक्ति को, जिसका निवास-स्थान या सरकारी कार्य स्थान सील्ड सड़क पर हो, उसके सरकारी यान हेतु, ऐसी सड़क के लिए, पास तभी दिया जा सकेगा यदि यह प्रतिबन्धित या अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (iii) सील्ड सड़क पर निवास-स्थान वाले सम्पत्ति कर दाता को, उसके स्वामित्व वाले यान हेतु ऐसी सड़क के लिए पास तभी दिया जा सकेगा यदि उसका निवास-स्थान किसी प्रतिबन्धित या अन्य सड़क द्वारा सुगम्य नहीं है और उसके पास ऐसे निवासीय प्रक्षेत्र में गैराज/पार्किंग सुविधा है:

परन्तु यह और कि सचिव (गृह) समय-समय पर लोक सुरक्षा और सुविधा के हित में, किसी सील्ड सड़क के लिए यातायात के क्रास संचलन (क्रास मूवमेंट) में बाधा न होने देने के लिए, यान की अधिकतम चौड़ाई (व्हील बेस) पर प्रतिबन्ध अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निवास-स्थान, यथास्थिति, प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क द्वारा सुगम्य समझा जाएगा यदि यह ऐसी सड़क से सौ मीटर की पथ दूरी के भीतर स्थित है।

(2) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट समस्त प्रतिबन्धित सड़कों, उच्च पदस्थों के यानों और उनके साथ चलने वाले सुरक्षा यानों तथा इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में निम्नलिखित यानों के सिवाए, समस्त मोटर यातायात के लिए बन्द होंगे, अर्थात्:—

- (i) लोक-उपयोगी यान जो राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा लोकहित में आवश्यक समझी जाएं;

- (ii) प्रमुख व्यक्ति के उपयोग के लिए एक सरकारी यान जहां विशिष्ट प्रतिबन्धित सड़क पर इसका चलाया जाना लोकहित में है :

परन्तु यह कि प्रमुख व्यक्तियों के यानों की बाबत तीन प्रतिबन्धित सड़कों तक के लिए ही पास दिए जा सकेंगे जहां प्रमुख व्यक्ति का लोकहित में प्रायः आना-जाना अपेक्षित है।

- (iii) अभिहित पार्किंग स्थलों या समादत पार्किंग लॉटों (पेड़ पार्किंग लॉट्स) से यात्रियों को लाने के लिए उस होटल या अन्य बोर्डिंग स्थानों की बाबत, जो किसी अन्य सड़क से सुगम्य न हो, दो यानों तक (उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या देते हुए); परन्तु यान होटल/बोर्डिंग स्थल के द्वारा स्वामित्वाधीन हो या कम से कम तीन मास की अवधि के लिए पट्टे पर हो;
- (iv) ऐसी प्रतिबन्धित सड़क पर स्थित सम्पत्ति में साधारणतया निवास करने वाले और जहां सम्पत्ति किसी अप्रतिबन्धित सड़क से सुगम्य नहीं है, गृहस्वामी या अधिभोगी की बाबत एक यान; और
- (v) निकटतम प्रतिबन्धित सड़क से उस कार्यालय तक युक्तियुक्त परिवहन पहुंच की व्यवस्था करने के लिए यदि कार्यालय किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है, तो सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों पर अवस्थित कार्यालयों से संलग्न सरकारी यान।

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई स्थान, किसी अन्य सड़क से सुगम्य समझा जाएगा यदि ऐसे मार्ग से यह सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित है।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का सचिव (गृह) यातायात के आवागमन (क्वाण्टम) और मार्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किए जाने वाले पासों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ताकि पैदल चलने वालों को खतरा, असुविधा या क्षोभ कारित न हो।

4. (1) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित रीति में, धारा 3 पासों का के अधीन विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों के अधीन और धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों जारी करना। पर, 'पास' जारी किए जाने पर यानों को अनुसूची-1 या 2 में विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाया जाना अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) पास, लोक हित में निवास या कार्य-स्थान को पहुंच प्रदान करने के लिए दिया जाएगा और सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क के उस भाग के लिए ही होगा जो निकटतम अप्रतिबन्धित सड़क पर पहुंच के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है।

(3) जहां प्रतिबन्धित सड़क पर स्थित सम्पत्ति में साधारणतया निवास करने वाले गृहस्वामियों या अधिभोगियों की बाबत प्रतिबन्धित सड़क के लिए पासों की अधिकतम संख्या नियत की गई है वहां निम्नलिखित को अधिमान दिया जाएगा,—

- (क) वरिष्ठ नागरिक और स्थायी रूप से निःशक्त (विकलांग);
- (ख) शिमला के सम्पत्ति कर देने वाले; और
- (ग) प्रख्यात समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के राज्य स्तरीय प्रत्यायित प्रेस संवाददाता जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित प्रत्यायन समिति द्वारा प्रत्यायन अनुदत्त किया गया हो:

परन्तु यह कि उनको अधिमान दिया जाएगा जिनका गैराज/निजी पार्किंग स्थान/ड्राइववेज या अन्य नियमित पार्किंग प्रबन्ध है और उपरोक्त (ख) और (ग) की बाबत पारस्परिक अधिमान, निवास पर उनकी रहने की समयावधि पर आधारित होगा:

परन्तु यह और कि सरकार निःशक्त व्यक्तियों की दशा में ऐसी प्रतिबन्धित सड़क के लिए इतने पास दे सकेगी जितने दी गई निःशक्तता के विस्तार तक, सुविधापूर्ण पहुंच के लिए अपेक्षित हों।

(4) सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क पर निवास होने के कारण प्रति परिवार/निवास को एक से अधिक पास नहीं दिया जाएगा और केवल यह तथ्य कि निवास/कार्य-स्थान सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क पर है, पास प्रदान करने का हकदार नहीं बनाएगा।

कतिपय
मामलों में
छूट।

5. प्रतिबन्धित सड़क पर रात ग्यारह बजे से सुबह सात बजे के बीच मोटर यान चलाने के लिए कोई पास अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह कि सरकार यानों और पैदल चलने वालों को क्षोभ या खतरे से निवारित करने के लिए किसी सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क की बाबत ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन (जिनके अन्तर्गत दिन में विनिर्दिष्ट समय के लिए सड़कों को इकतरफा या नो ट्रैफिक रोड घोषित करना है) जैसे कि विशिष्ट सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, अधिरोपित कर सकेगी।

सील्ड सड़कों
के लिए
पास प्रदान
करने और
नवीकरण
करने हेतु
आवेदन तथा
प्रक्रिया।

6. (1) सील्ड सड़कों पर यान चलाने के लिए पास देने हेतु आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और उसे राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को सम्बोधित किया जाएगा।

(2) सील्ड सड़कों पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रोसेसिंग के लिए सरकारी यान की दशा में सौ रुपये और निजी (प्राइवेट) यान की दशा में पांच सौ रुपये की अप्रतिदेय फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह कि किसी सरकारी यान के लिए पास देने हेतु एक हजार रुपये और निजी (प्राइवेट) यान के लिए पास देने हेतु दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष, प्रति सड़क, फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि लोक-उपयोगी यानों से कोई भी फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(3) किसी सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन) या कार्यालय के प्रधान से इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि यान सम्बद्ध अधिकारी के साथ अभिनियोजित किया गया है;
- (ख) आवेदक द्वारा इस प्रभाव का स्वतः प्रमाणन कि कार्यालय/निवास सील्ड सड़क पर है और यह किसी प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (ग) प्रोसेसिंग फीस के संदाय का सबूत; और
- (घ) ऐसे अन्य दस्तावेज जैसे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) निजी (प्राइवेट) यान के लिए पास प्रदान करने हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित फोटोकॉपी सबूत के रूप में कि आवेदक यान का स्वामी है;
- (ख) आवेदक का सील्ड सड़क पर निवास का स्वतः प्रमाणित किया हुआ सबूत;
- (ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि सील्ड सड़क पर निवास किसी भी प्रतिबन्धित सड़क या किसी अन्य सड़क से सुगम्य नहीं है और आवेदक का अपना स्वयं का गैराज या पार्किंग सुविधा है;
- (घ) प्रोसेसिंग फीस के संदाय का सबूत;
- (ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जैसे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) समस्त आवेदन इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत, रजिस्ट्रीकृत और प्रोसेस किए जाएंगे।

(6) सील्ड सड़क के लिए पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी के, हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) से नीचे की पंक्ति का न हो, विहित फीस के संदाय के पर जारी किया जाएगा और पास का सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए; और पास को यान की विन्ड-स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि पास एक से अधिक सील्ड सड़क की बाबत जारी किया गया है तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में जैसा कि अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इसके लिए संदेय विहित फीस के संदाय पर जारी किया जा सकेगा।

(7) किसी यान को सील्ड सड़क पर चलाने के लिए पास को, गृह विभाग द्वारा, इस अधिनियम की धारा 6 (2) में यथा उपबन्धित, फीस के संदाय पर, प्रतिवर्ष नवीकृत किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन पूर्ववर्ती पास/दस्तावेज की फोटो-प्रतिलिपि के साथ किया जाएगा और यदि आवेदक इसकी विधिमान्यता अवधि के अवन्यून से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तो, पास व्यपगत (समाप्त) हो जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक यह साबित कर देता है कि उसके पास नवीकरण के लिए समय पर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे तो पास निर्धारित फीस के संदाय पर, दो सौ रुपये प्रतिमास की बिलम्ब फीस सहित नवीकृत कर दिया जाएगा।

प्रतिबन्धित
सड़कों के
लिए पास
प्रदान करने
और
नवीकरण
करने हेतु
आवेदन तथा
प्रक्रिया।

7. (1) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने के लिए पास प्रदान करने हेतु आवेदन, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को प्रेषित किया जाएगा।

(2) प्रतिबन्धित सड़क पर यान चलाने हेतु पास के मामले की प्रोसेसिंग लिए सरकारी यान से सौ रुपये और निजी (प्राइवेट) यान से पांच सौ रुपये की अप्रतिदेय प्रोसेसिंग फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह कि सरकारी यान के लिए पास प्रदान करने हेतु एक हजार रुपये और निजी (प्राइवेट) यान के लिए पास प्रदान करने हेतु दो हजार रुपये प्रति सड़क, प्रतिवर्ष, फीस प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि लोक-उपयोगी यानों से कोई भी फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(3) सरकारी यान के लिए प्रतिबन्धित सड़क का पास प्रदान करने हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) यथास्थिति, राज्य सरकार के सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) या कार्यालय के प्रधान द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण—पत्र कि यान, सम्बद्ध प्रमुख व्यक्ति के साथ लगा हुआ है;
- (ख) सचिव (सामान्य प्रशासन) विभाग या कार्यालय के प्रधान द्वारा इस प्रभाव का स्वतः प्रमाणन कि कार्यालय/निवास, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर है और किसी भी प्रतिबन्धित या अन्य किसी सड़क से सुगम्य नहीं है;
- (ग) प्रोसेसिंग फीस के संदाय का सबूत; और
- (घ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) निजी (प्राइवेट) यान के लिए प्रतिबन्धित सड़क का पास प्रदान करने हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) आवेदक के यान का स्वामी होने के सबूत के रूप में, यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र की अनुप्रमाणित फोटो—प्रतिलिपि;
- (ख) आवेदक के निवास का, यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर होने के सबूत का दस्तावेज;
- (ग) उपायुक्त शिमला के कार्यालय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण—पत्र कि यथास्थिति, सील्ड या प्रतिबन्धित सड़क पर निवास, किसी भी अप्रतिबन्धित मार्ग से सुगम्य नहीं है, और आवेदक का अपना गैराज है या नियमित पार्किंग स्थान की उसके पास सुविधा है;
- (घ) फीस के संदाय का सबूत; और
- (ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) समस्त आवेदन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अभिस्वीकृत, रजिस्ट्रीकृत और प्रोसेस किए जाएंगे।

(6) प्रतिबन्धित सड़क के लिए पास को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, सरकार के अधिकारी के, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) से नीचे की पंक्ति का न हो, या सहायक आयुक्त शिमला मण्डल के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन निर्धारित फीस के संदाय के पश्चात् जारी किया जाएगा और जिसका सुभिन्न रंग और आकार होगा, जैसा गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए; और इसे यान की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यदि पास एक से अधिक प्रतिबन्धित सड़क की बाबत जारी किया गया है तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इसके लिए संदेय विहित फीस के संदाय पर, जारी किया जाएगा।

(7) किसी यान को प्रतिबन्धित सड़क पर चलाने के लिए पास को, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम की धारा 7 (2) में यथा उपबन्धित, फीस के संदाय पर, प्रतिवर्ष नवीकृत किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन पूर्ववर्ती पास/दस्तावेज की अनुप्रमाणित फोटो-प्रतिलिपि के साथ किया जाएगा और यदि आवेदक इसकी विधिमान्यता अवधि के अवसान से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तो, पास व्यपगत (समाप्त) हो जाएगा:

परन्तु यदि आवेदक यह साबित कर देता है कि उसके पास नवीकरण के लिए समय पर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे तो पास निर्धारित फीस के संदाय पर, दो सौ रुपये प्रतिमास की बिलम्ब फीस सहित नवीकृत कर दिया जाएगा।

साधारण शर्तें।

8. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पास, निम्नलिखित साधारण निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपान्तरित किया जा सकेगा, प्रदान किए जाएंगे:—

(क) सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों पर बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक की गति से यान नहीं चलाए जाएंगे और गतिसीमा का उल्लंघन करने वाले यान का पता चलने पर उसका पास रद्द किए जाने के लिए दायी होगा;

(ख) व्यक्ति जिन्हें सील्ड या प्रतिबन्धित सड़कों के लिए पास प्रदान किए गए हैं, अपने यान केवल निजी (प्राइवेट) परिसरों या अनुज्ञात पार्किंग स्थानों पर ऐसी रीति में खड़ा करेंगे ताकि पैदल चलने वाले या दूसरे यानों को क्षोभ या खतरा कारित न हो और सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों पर अप्राधिकृत रूप से या खतरनाक तरीके से खड़े पाए गए यानों के पास रद्द किए जाने के लिए दायी होंगे;

(ग) किसी यान के स्वामी का सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क का पास धारण करना ही किसी भी रीति में उपर्युक्त सड़कों में से किसी पर भी यान खड़ा करने का अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा;

- (घ) यान, अनुज्ञात पार्किंग स्थानों और समादत पार्किंग स्थानों (पेड् पार्किंग लॉटस) के सिवाय सील्ड/प्रतिबन्धित मार्गों पर खड़े नहीं किए जाएंगे;
- (ङ) जिन यानों को सील्ड सड़कों के पास प्रदान किए गए हैं, सड़कों पर तभी चलाए जाएंगे यदि व्यक्ति, जिसके पक्ष में पास प्रदान किया गया है वह स्वयं या उसका/उसकी पति/पत्नी यान में बैठा हुआ है/बैठी हुई है या यदि यान चालक (शॉफर) द्वारा चलाया जाने वाला है, तो उसका चलाया जाना केवल पास धारक/उसके पति या पत्नी को लाने के आशय से होंगे;
- (च) वैध पास यान के विण्ड स्क्रीन पर चिपकाए जाएंगे और पास धारक सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों पर, यातायात पुलिस को जांच स्थलों पर, पास की जांच करने के लिए यान की गति को धीमी करेगा;
- (छ) पास केवल अनुज्ञात सड़क पर विधिमन्यता अवधि के दौरान ही उपयोग में लाएं जाएंगे;
- (ज) अवसित (समाप्त) पास प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे; और
- (झ) पास का दुरुपयोग, पास धारक के सभी या किन्ही वैध पासों को रद्द करना अपरिहार्य बना देगा।

9. (1) सील्ड सड़क के लिए अस्थायी पास सरकारी समारोहों (ऑफिशियल कतिपय फंक्शन) आदि के कारण, राज्य से बाहर के उच्च पदस्थ व्यक्ति या प्रमुख व्यक्ति को लोकहित में जारी किया जाएगा, जो किसी सरकारी समारोह में ऐसे स्थल पर भाग ले रहा है जो ऐसी सील्ड सड़क से ही सुगम्य हो और जहां स्थल, यथास्थिति, सील्ड सड़क या किसी अन्य सड़क से सौ मीटर से अनधिक की पथदूरीस्वरूप सुगम्य न हो।

(2) सील्ड सड़क के लिए ऐसे अस्थायी पास का आवेदन, दो सौ रुपये प्रतिदिन की फीस के संदाय पर, अधिकतम सात दिन के लिए, राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, कम से कम दो दिन अग्रिम में, समर्थक दस्तावेजों के साथ किया जाएगा और पास ऐसे प्ररूप में, जैसा कि समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी अधिकारी, जो राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) से नीचे की पंक्ति का न हो, के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन जारी किया जाएगा; और उक्त पास का सुभिन्न रंग और आकार होगा, जिसे गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए; और उसे यान की विण्ड-स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि पास एक से अधिक सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों के लिए जारी किया गया है, तो एक समेकित पास, ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा।

(3) प्रतिबन्धित सड़क के लिए अस्थायी पास राज्य सरकार के अवर सचिव (गृह) को किए गए आवेदन पर ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके समर्थन में दिए गए कारणों सहित, प्रतिदिन सौ रुपये की फीस के संदाय पर, अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। आवेदन तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जहां पैदल चलने वालों को कोई खतरा या क्षोभ कारित होने की सम्भावना न हो :

परन्तु यह कि गृह अधिभोगी को चिकित्सीय या अन्य आपातक आधारों पर भी प्रतिबन्धित सड़क के लिए अस्थायी पास, ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के अवर सचिव (गृह) की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे प्ररूप में जारी किया जा सकेगा जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और उक्त पास का सुभिन्न रंग और आकार होगा, जिसे गृह विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और उसे यान की विण्ड-स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि पास एक से अधिक सील्ड/प्रतिबन्धित सड़क के लिए जारी किया गया है, तो समेकित पास ऐसे प्ररूप में, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी किया जाएगा।

(4) फिल्मों के फिल्मांकन (शूटिंग) के प्रयोजनार्थ या किसी वाणिज्यिक या मनोरंजन के प्रयोजनार्थ सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के लिए अस्थायी पास राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा अधिकतम दस यानों तक प्रतियान तीन हजार रुपये की फीस के संदाय पर, सात दिन की अधिकतम अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह कि पैदल चलने वालों को किसी खतरे या क्षोभ से निवारित करने के लिए, पास को जारी करते समय इसकी विधिमान्यता के घण्टों और पार्किंग निर्बन्धनों के सम्बन्ध में शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी।

इस अधिनियम

10. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए उपायुक्त शिमला/पुलिस

के उपबन्धों का अधीक्षक शिमला निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि—

प्रवर्तन।

- (क) समस्त सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों के प्रवेश स्थलों और सहजदृश्य स्थलों पर संकेतों की व्यवस्था है जो सड़क का नाम और इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों को उपदर्शित करती है;
- (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए व्यस्ततम समय पर पर्याप्त यातायात पुलिस अभिनियोजित की गई है;
- (ग) सील्ड सड़कों में सामरिक (स्ट्रेटीजिक) स्थलों पर बैरियरों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यान ऐसी सड़कों का उपयोग आम रास्ते के रूप में या यान को अधिक गति से चलाने के लिए न करें; और
- (घ) सील्ड/प्रतिबन्धित सड़कों पर चलने वाले यानों की निरन्तर अन्तरालों पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, स्थल पर ही जांच (चैकिंग) है।

11. (1) जो कोई पास के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता शास्ति। है, तो उसे दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे एक मास का साधारण कारावास भुगतना होगा:

परन्तु यह कि ऐसे प्रत्येक अपराध का पुलिस अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, एक हजार रुपये की प्रशमन फीस के साथ शमन किया जा सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधधीन रहते हुए, जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो उसे तीन हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा या उसके व्यतिक्रम में उसे एक मास का साधारण कारावास भुगतना होगा:

परन्तु यह कि अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पन्द्रह सौ रुपये की प्रशमन फीस के साथ अपराध का शमन कर सकेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति प्रशमन फीस का संदाय करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति सहित यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र परिबद्ध किया जाएगा और मामले को अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

12. (1) यदि किसी पास धारक को पास के निबन्धनों और शर्तों का पासों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो धारा 11 के अधीन उपबन्धित किसी शास्ति के रद्दकरण। अतिरिक्त पास को राज्य सरकार के सचिव (गृह) द्वारा रद्द किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि रद्दकरण का ऐसा कोई भी आदेश, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपायुक्त शिमला/पुलिस अधीक्षक शिमला पास धारक द्वारा इस अधिनियम के किसी अतिल्लंघन, जो पास को रद्दकरण के लिए दायी बनाता है, का पता चलने पर उसकी सूचना गृह विभाग को देगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसका पास, इसके (पास के) निबन्धनों और शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है, तो वह रद्दकरण आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसी यान के लिए उसके नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी पास को प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

13. (1) न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील, अधिकारिता रखने अपील। वाले सत्र न्यायाधीश को, उक्त आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जा सकेगी।

(2) पास के रद्दकरण के विरुद्ध अपील राज्य सरकार के, यथास्थिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) या प्रधान सचिव (गृह) को, रद्दकरण आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर की जा सकेगी।

फीस और
जुर्माने के
आगमों का
उपयोग।

14. (1) ऐसी तारीख से, जैसी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए सुख-सुविधा निधि” के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(2) निधि का सीलड और प्रतिबंधित सड़कों के साथ पैदल चलने वालों की सुख-सुविधाओं, पैदल चलने वालों की सुरक्षा में सुधार, निवासियों के लिए रियायती दरों सहित सुविधाजनक पार्किंग स्थलों के विकास, प्रवेश नियन्त्रण, मॉनिटरिंग उपकरणों इत्यादि के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा, ताकि सीलड और प्रतिबंधित सड़कों पर यानीय गति को विनियमित किया जा सके और पैदल चलने वालों के संभाव्य खतरे या क्षोभ को कम किया जा सके।

(3) निधि को मण्डलायुक्त शिमला की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा जिसमें आयुक्त, नगर निगम शिमला, उपायुक्त, शिमला और पुलिस अधीक्षक, शिमला भी सम्मिलित होंगे।

(4) समिति,—

(i) सीलड या/प्रतिबंधित सड़कों में सड़कों को सम्मिलित करने/इनमें से इन्हें निकालने की सिफारिश कर सकेगी;

(ii) पार्किंग स्थानों के लिए स्थलों की सिफारिश कर सकेगी;

(iii) निधि में जमा धन के उपयोग के लिए प्रस्तावों का शोधन और उनकी प्रगति मॉनीटर कर सकेगी;

(iv) इस अधिनियम के प्रवर्तन को मॉनीटर कर सकेगी; और

(v) ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप कार्यान्वित कर सकेगी, जो विहित किए जाएं।

(5) इस अधिनियम के अधीन जमा फीस और जुर्माने के आगम राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और निधि से ऐसी रीति में, जैसी समय-समय पर विनिश्चित की जाए, निधि के अनुसार विनियोजित किए जाएंगे।

15. राज्य सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 अनुसूचियों को या अनुसूची-2 में से, उनमें विनिर्दिष्ट किन्हीं सड़कों में किसी को सम्मिलित कर सकेगी संशोधित करने की शक्ति। या उनमें से किसी को निकाल सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूचियां तदनुसार संशोधित हो जाएंगी।

16. राज्य सरकार ऐसे कारणों से, जो लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे, शिथिल करने लोकहित में, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को, पासों के किसी भी प्रवर्ग के लिए, की शक्ति। एक बार में सात दिन से अनधिक अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी।

17. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन आने वाले अधिकारिता मामलों से सम्बन्धित प्रश्नों को ग्रहण करने या उन का विनिश्चय करने की कोई का वर्जन। अधिकारिता या शक्ति नहीं होगी।

18. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई कठिनाईयों उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर का दूर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों और जो इसे, कठिनाई को किया जाना। दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

19. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को नियम बनाने कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उक्त सत्रों जिनमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपर्युक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमन्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों अन्य के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। विधियों का वर्जित न होना।

21. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन की गई या कार्यवाई के लिए या अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होंगी। संरक्षण।

निरसन और
व्यावृत्तियाँ।

22. गृह विभाग के पृष्ठांकन संख्या गृह-ग (ई) -2-1/2000, तारीख 20 दिसम्बर, 2003 द्वारा सील्ड और प्रतिबन्धित सड़कों पर यातायात को विनियमित करने के लिए जारी की गई पॉलिसी गाइडलाइनज और इस निमित्त समय-समय पर जारी की गई अन्य गाइडलाइनज, अधिसूचनाएं या आदेशों का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित पॉलिसी गाइडलाइनज, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन की गई कोई कार्यवाई या बात, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची-1

(धारा 2 और 3 देखें)

सीलड सड़कों की सूची

रोड़ कोड	सड़क का नाम
1	2
एस-1.	छोटा शिमला चौक से ऑक ओवर तक ।
एस-2.	ऑक ओवर से शैलेट-डे-स्कूल तक ।
एस-3.	शैलेट-डे-स्कूल से मैट्रोपोल होटल तक ।
एस-4.	इंदिरा गाँधी अस्पताल की लोअर बाइफरकेशन से लक्कड़ बाजार तक ।
एस-5.	जोधा निवास से रिज तक ।
एस-6.	माल रोड़ से रिज की तरफ जाने वाली समस्त सम्बन्धन (कनेक्टिंग) सड़कें ।
एस-7.	होटल व्हाइट से रीगल सिनेमा/रिज तक ।
एस-8.	कनैडी हाउस चौक से गॉरटन कैसल तक ।
एस-9.	रेलवे बोर्ड भवन से सैनिक प्रशिक्षण कम्प्लेक्स तक ।
एस-10.	तारा हॉल स्कूल से लिंक रोड़ कालीबाड़ी की ओर क्रॉस करते हुए शिमला टाइपराईटर कम्पनी तक, माल रोड़ को जोड़ते हुए ।
एस-11.	स्कैण्डल प्वाइंट से कालीबाड़ी तक ।

टिप्पणः—केन्द्रीय तारघर (ऊपर और नीचे दोनों तरफ की) से माल रोड़ होते हुए रिज तक [विशेषतः चर्च के एक तरफ जोधा निवास के नीचे लेडीज पार्क पार्किंग और दूसरी तरफ जाखू से रीगल सिनेमा की तरफ मुड़ने वाला मार्ग (रूट)] और कोर माल रोड़ फोरम हुए केन्द्रीय तारघर से शिमला क्लब तक जाने वाली सड़कें, उच्च पदस्थों और लोकोपयोगिता के यानों के सिवाए समस्त यातायात के लिए प्रतिषिद्ध होंगी और ऐसी सड़कों के लिए संकर्म या निवास के आधार पर कोई पास जारी नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची-2

(धारा 2 और 3 देखें)

प्रतिबन्धित सड़कों की सूची

रोड कोड	सड़क का नाम
1	2
आर-1.	कनैडी हाउस चौक से पुलिस स्टेशन चौक, से पीटर हॉफ/ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन/भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान तक।
आर-2.	पीटरहॉफ/ऑल इण्डिया रेडियो स्टेशन/भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से बालूगंज तक।
आर-3.	कार्ट रोड से उपायुक्त कार्यालय तक।
आर-4.	कार्ट रोड से सब्जी मंडी तक।
आर-5.	संजौली चौक से लोअर बाइफरकेशन इंदिरा गांधी अस्पताल (लक्कड़ बाजार) तक।
आर-6.	फॉरेस्ट लॉज से (रामचन्द्र चौक) वाया यू0एस0 क्लब जोधा निवास तक।
आर-7.	कार्ट रोड से गॉरटन कैसल तक।

टिप्पण.—निम्नलिखित सड़कें केवल छोटे यानों के लिए खुली रहेंगी जिनके लिए किसी अनुज्ञा-पत्र (परमिट) की आवश्यकता नहीं होगी:—

1. कार्ट रोड से मैडिकल कॉलेज की ओर से इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज अस्पताल तक लिंक रोड।
2. सैंट बीडज कॉलेज चौक से फॉरेस्ट लॉज तक।
3. कार्ट रोड से अग्निशमन उपकेन्द्र छोटा शिमला तक, बैनमोर से ऑक औवर चौक तक।
4. कार्ट रोड (सैंट एडवर्ड स्कूल के पास) से मैरीना होटल तक।
5. कार्ट रोड से कनैडी हाउस चौक होते हुए अनाडेल तक।

THE SHIMLA ROAD USERS AND PEDESTRIANS (PUBLIC SAFETY AND CONVENIENCE) BILL, 2006

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for regulation of vehicular traffic in the interest of public safety and convenience on the sealed and restricted roads of Shimla town to prevent annoyance and injury to pedestrians and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2006. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the Municipal limits of Shimla Town.

(3) It shall come into force at once.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(a) 'Act' means the Shimla Road Users and Pedestrians (Public Safety and Convenience) Act, 2006;

(b) 'Assistant Commissioner' means Assistant Commissioner, appointed by the State Government under section 9 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953;

(c) 'Deputy Commissioner' means the Chief Officer-in-charge of the general administration of a District;

(d) 'Divisional Commissioner' means the Divisional Commissioner of Shimla Revenue Division;

(e) 'fees' means the amount chargeable for processing and grant of a pass under this Act;

- (f) 'Fund' means the "Shimla Road Users and Pedestrian Amenities Fund" established under section 14 of this Act;
- (g) 'Head of Department' means the authority specified in Schedule-I to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 and includes such other authority or person as the State Government may, by order, specify as the Head of a Department;
- (h) 'Head of Office' means a Gazetted Officer declared as such under Rule 14 of the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, and includes such other authority or person as the competent authority may, by order, specify as Head of Office;
- (i) 'High Dignitaries means,—
- (i) The President of India;
 - (ii) The Vice President of India;
 - (iii) The Prime Minister of India;
 - (iv) The Chief Justice of India;
 - (v) The Governor of Himachal Pradesh;
 - (vi) The Judges of the Supreme Court of India;
 - (vii) The Speaker of the Lok Sabha;
 - (viii) The Chief Minister of Himachal Pradesh;
 - (ix) The Speaker of the Himachal Pradesh State Legislative Assembly;
 - (x) The Chief Justice of Himachal Pradesh High Court;
 - (xi) The Ministers of Himachal Pradesh;
 - (xii) The Judges of Himachal Pradesh High Court;
 - (xiii) The Former Chief Ministers of Himachal Pradesh; and
 - (xiv) The Chiefs of Staff of the Army, Air force and Navy;
- (j) 'pass' means a pass issued under this Act for driving of a vehicle on a sealed or restricted road, or both, as the case may be;
- (k) Prominent person means,—
- (i) The Advocate General of Himachal Pradesh;
 - (ii) The Members of Parliament and Legislative Assembly of Himachal Pradesh;

- (iii) Chief Secretary/Additional Chief Secretary to the State Government;
 - (iv) General Officer Commanding- in-Chief, Army Training Command;
 - (v) Central and State Government officers, in Super Time Scale or above, posted in Shimla;
 - (vi) Judicial Officers of the State, in Super Time Scale, posted in Shimla;
 - (vii) The Military Officers of the rank of Major General and above, posted in Shimla;
 - (viii) The Mayor and Councilors, Municipal Corporation, Shimla; and
 - (ix) Full time Chairmen and Members of Boards, Corporations or Statutory Commissions of Himachal Pradesh, in Super Time Scale and above;
- (l) 'Public utility vehicles' means the following vehicles, used or being used for carrying out essential services:—
- (i) Fire fighting vehicles;
 - (ii) Ambulances and dead body vans;
 - (iii) Postal Mail vehicles;
 - (iv) Vehicles deployed for maintenance of communications and other public services or public transport vehicles, approved by Home Department;
 - (v) Vehicles deployed for maintenance of sanitation, water supply and other civic services by the Municipal Corporation, Shimla including official vehicles used by the Municipal Corporation officers for day to day inspection and maintenance of the said duties; and
 - (vi) Heavy vehicles belonging to the Central Public Works Department, Himachal Pradesh Public Works Department, Himachal Pradesh State Electricity Board, Irrigation and Public Health Department and Municipal Corporation Shimla etc. deployed for execution of any construction or maintenance activities;
 - (vii) Official vehicles required for law and order and for protocol duty with High Dignitaries by the District Administration, Shimla and the General Administration Department of the State Government;
- (m) 'restricted road' means a road specified in Schedule-II;

- (n) 'Schedule' means a Schedule appended to this Act;
- (o) 'sealed road' means a road specified in Schedule-I,
- (p) 'State' means the State of Himachal Pradesh;
- (q) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
- (r) 'Super Time Scale' means the pay scale of Rs.18400-22400.

(2) All other words and expressions used, but not defined in this Act and defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988), shall have the same meaning respectively assigned to them in that Act.

Restrictions
on the use
of vehicles
on sealed
and
restricted
roads

3. (1) All sealed roads specified in Schedule-I shall be sealed to all motorized traffic, except vehicles of High Dignitaries and accompanying security vehicles, and no person shall drive a vehicle on the roads specified in Schedule-I without a pass obtained by him under this Act,

Provided that,—

- (i) passes may be issued to such public utility vehicle, as deemed necessary in the public interest, by Secretary (Home) from time to time;
- (ii) a prominent person having his residence or official work place on a sealed road may be given a pass for his official vehicle for such road only if it is not approachable from a restricted or other road; and
- (iii) a property tax payer having residence on a Sealed road may be given a pass for a vehicle owned by him for such road only in case his residence is not approachable through any restricted or other road and he has a garage/ parking facility in such residential complex;

Provided further that the Secretary (Home) may from time to time impose restrictions on the maximum width (wheel base) of a vehicle for any sealed road in the interest of public safety and convenience, so as to prevent hindrance to cross movement of traffic.

Explanation.—For the purposes of this Act a residence shall be deemed to be approachable through a restricted road or any other road, as the case may be, if it is situated within path distance of 100 meters from such road.

(2) All restricted roads specified in Schedule-II shall be closed to all motorized traffic, except vehicles of High Dignitaries and their accompanying

security vehicles and the following vehicles in the manner provided in this Act, namely: --

- (i) Public utility vehicles as deemed necessary in the public interest by Secretary (Home) to the State Government; and
- (ii) One official vehicle for the use of a prominent person where its plying on a particular restricted road is in the public interest:

Provided that in respect of vehicles of prominent persons, passes upto 3 restricted roads may be given where the prominent person is required to frequently visit in the public interest;

- (iii) Up to two vehicles (giving registration numbers thereof) in respect of a Hotel or other boarding places not approachable from any other road, in order to carry guests from designated parking places or paid parking lots; provided that the vehicle is owned or leased by the Hotel/boarding place for a period of not less than 3 months;
- (iv) One vehicle in respect of a house-owner or occupier ordinarily resident in a property situated on such restricted road and where the property is not approachable from any un-restricted road; and
- (v) Official vehicles attached to offices located on sealed or restricted roads, in order to provide reasonable transport access upto that office through the nearest restricted road, in case the office is not approachable from any other road.

Explanation.—For the purposes of this Act, a place shall be deemed to be approachable through any other road, if it is situated within a distance of 100 meters from such road.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Secretary (Home) to the State Government, may specify a maximum number of passes to be issued for a particular restricted road, keeping in view the quantum of traffic and nature of road, so as not to cause danger, inconvenience or annoyance to the pedestrians.

4. (1) Vehicles shall be allowed to use roads specified in Schedule I or II on grant of a 'pass' by the State Government in the manner provided in this Act, subject to restrictions specified under section 3 and on general conditions specified under section 8. Issue of passes.

(2) The pass shall be granted to provide access to residence or to the work place in the public interest and shall be for only that portion of the sealed or restricted road that is reasonably required to access the nearest un-restricted road.

(1) Where the maximum number of passes has been fixed for a restricted road in respect of house owners or occupiers ordinarily resident in a property situated on a restricted road, preference will be given to

- (a) senior citizens and permanently disabled;
- (b) property tax payers of similar; and
- (c) State level accredited Press Correspondents of reputed newspapers and journalists who have been accredited accreditation by an Accreditation Committee duly constituted by the State Government.

Provided that preference may be given to those with garages/private parking places/ driveways or other regular parking arrangements and further in respect of (b) and (c) above, such preference shall be based on length of stay at the residence.

Provided further that the Government may in the case of disabled persons grant the pass for such restricted road as may be required to provide convenient access giving the extent of disablement.

(4) Not more than one pass shall be issued per family/residence on the grounds of residence on a sealed/restricted road, and the mere fact that the residence/work place is on a sealed/restricted road shall not entitle the grant of a pass.

Exception in certain cases.

5. No pass shall be required to drive a motor vehicle between 11.00 A.M. to 7.00 P.M. on a restricted road.

Provided that Government in order to prevent annoyance or danger to vehicles and pedestrians may impose such reasonable restrictions (including restriction of roads as one way or no traffic roads for specified times of the day) in respect of any sealed or restricted road as may be necessary having regard to the circumstances of a particular sealed/restricted road.

Application for grant and renewal of pass for sealed road and private

6. (1) Application for grant of a pass for driving a vehicle on a sealed road shall be made in such form as may be specified by notification, and shall be addressed to the Union Secretary (Home) in the State Government.

(2) A non refundable fee of Rs. 100 for an official vehicle and Rs. 500 for a private vehicle shall be charged for processing of cases for a pass for driving of vehicle on sealed roads.

Provided that a fee of Rs. 1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs. 2500 for grant of a pass for a private vehicle per road, per annum.

provided further that no fee shall be chargeable from public utility vehicles.

(13) The application for grant of a pass for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:

- (a) A certificate from Secretary (17/13) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is deployed with the utmost care;
- (b) Self attestation by the applicant to the effect that the office residence is on a sealed road and is not approachable from any of the restricted or any other roads;
- (c) Proof of payment of the processing fee; and
- (d) Such other documents as may be specified by notification.

(14) The application for grant of a pass for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle to prove that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Self attested proof of residence of the applicant on the sealed road;
- (c) Certificate from the duly authorized officer of the office of Deputy Commissioner, Shindia to the effect that the residence on the sealed road is not approachable from any of the restricted roads or any other road and that the applicant has his own garage or has a parking facility;
- (d) Proof of payment of the processing fee; and
- (e) Such other documents as may be specified by notification.

(15) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(16) A pass for a sealed road shall be issued, in such form as may be specified by notification under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (11/11) to the State Government on payment of

the prescribed fee, and the pass shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and the pass shall be displayed on wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one sealed road, a consolidated pass may be issued on payment of the prescribed fee payable therefore in such form, as may be specified by a notification.

(7) The pass for driving a vehicle on a sealed road may be renewed annually by the Home Department on payment of a fee as provided in section 6 (2) of the Act and the application for such renewal shall be accompanied by photocopy of the previous pass/document, and in case the applicant does not make an application for renewal before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of the prescribed fee alongwith a late fee of Rs. 200 per month.

Application
for grant
and
renewal of
pass for
restricted
road and
procedure.

7. (1) An application for grant of a pass for driving a vehicle on a restricted road shall be made, in such form as may be specified by notification, addressed to Under Secretary (Home) to the State Government.

(2) A non-refundable fee of Rs. 100 for an official vehicle and Rs. 500 for a private vehicle shall be charged for processing of a case for a pass for driving of a vehicle on a restricted road:

Provided that a fee of Rs. 1000 shall be charged for grant of a pass for an official vehicle and Rs. 2000 shall be charged for grant of a pass for a private vehicle, per road, per annum:

Provided further that no fee shall be chargeable from public utility vehicles.

(3) The application for grant of pass for a restricted road for an official vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) A certificate by the Secretary (GAD) to the State Government or the Head of the Office, as the case may be, to the effect that the vehicle is attached with the concerned prominent person;
- (b) Self-Certification by Secretary (GAD) or the Head of the Office to the effect that the office/residence is on a sealed or restricted

road, as the case may be, and is not approachable from any of the restricted or any other roads;

- (c) Proof of payment of processing fee; and
- (d) Such other documents as may be specified by notification.

(4) The application for grant of a pass for a restricted road for a private vehicle shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) Attested photocopy of the Registration Certificate of the vehicle in proof that the applicant is the owner of the vehicle;
- (b) Document in proof of residence of the applicant on sealed or restricted road, as the case may be;
- (c) Certificate from the duly authorized officer of the office of the Deputy Commissioner, Shimla to the effect that the residence on the sealed or restricted road, as the case may be, is not approachable from any of the unrestricted roads and that the applicant has his own garage or has a facility of a regular parking place;
- (d) Proof of payment of fee; and
- (e) Such other documents as may be specified by notification.

(5) All applications shall be acknowledged, registered and processed under the provisions of this Act.

(6) A pass for a restricted road shall be issued, after payment of the prescribed fee, in such form as may be specified by notification under the signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government or Assistant Commissioner, Shimla Division and shall have a distinct colour and shape, as may be determined by the Home Department from time to time; and shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued in respect of more than one restricted road, a consolidated pass shall be issued on payment of prescribed fee payable therefor in such form as may be specified by notification.

(7) The pass for driving a vehicle on a restricted road may be renewed annually by the issuing authority on payment of the fee as provided in section 7(2) of this Act and the application for such renewal shall be accompanied by an attested photocopy of the previous pass/document and in case the application for renewal is not made by the applicant before the expiry of its validity period, the pass shall stand lapsed:

Provided that if the applicant proves that there were sufficient reasons for not making an application for renewal in time, the pass may be renewed on payment of the prescribed fee alongwith a late fee of Rs. 200 per month.

General
conditions.

8. Save as otherwise provided in this Act, passes shall be granted on the following general terms and conditions, which may be modified by the State Government, by notification:—

- (a) Vehicles shall not ply on the sealed/restricted roads at a speed of more than 20 K.M. per hour and the pass of a vehicle detected violating the speed limit shall be liable to be cancelled;
- (b) Persons granted sealed or restricted road passes shall park their vehicles in private premises or at permitted parking places only and in a manner so as not to cause annoyance or danger to other vehicles and pedestrians and passes of vehicles found unauthorizedly or dangerously parked along sealed/restricted roads shall be liable to be cancelled;
- (c) Mere holding of a sealed/restricted road pass by a vehicle owner shall not in any manner confer any right of parking a vehicle on any of the said roads;
- (d) Vehicles shall not be parked on sealed/restricted roads except at permitted parking places and paid parking lots;
- (e) Vehicles granted sealed road passes shall ply only when the person in favour of whom the pass is granted or his spouse is seated in the vehicle or in case the vehicle is a chauffeur driven vehicle, plying with the intention of picking up the pass holder/spouse;
- (f) Valid passes shall be pasted to the wind screen of the vehicle and the pass holder shall slow down the vehicle at check points on the sealed/ restricted roads to enable traffic police to inspect the pass;

- (g) Passes shall be used only on the permitted road and only during validity period;
- (h) Expired passes shall not be displayed; and
- (i) Misuse of pass shall entail cancellation of all or any valid passes of the pass holder.

9. (1) A temporary pass may be issued in the public interest for a sealed road on account of official functions etc. to a Dignitary from outside the State or a Prominent Person attending an official function at a venue approachable only from such sealed road and where the venue is not approachable by way of path distance not exceeding 100 meters from a restricted road or any other roads, as the case may be.

Grant of temporary passes in certain circumstances.

(2) Such temporary pass for a sealed road may be issued on payment of fee of Rs. 200 per day for maximum of seven days on an application made to the Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification at least 2 days in advance with supporting documentation and the pass shall be issued in such form as may be specified by a notification issued from time to time under signatures and seal of an officer not below the rank of the Under Secretary (Home) to the State Government; and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the Home Department from time to time; and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided that if the pass is issued for more than one sealed /restricted roads, a consolidated pass shall be issued in such form as may be specified by notification.

(3) A temporary pass for a restricted road may be issued on payment of a fee of Rs. 100 per day, for a maximum period of 7 days, on an application made to Under Secretary (Home) to the State Government in such form as may be specified by notification, with reasons in support thereof. The application may be accepted in case plying of the vehicle is not likely to cause danger or annoyance to pedestrians:

Provided that a house occupier on medical or other emergent grounds may also be granted a temporary pass for a restricted road to be issued in such form as may be specified by notification under signatures and seal of an officer not below the rank of Under Secretary (Home) to the State Government and the said pass shall have a distinct colour and shape, as determined by the

Home Department from time to time and the same shall be displayed on the wind screen of the vehicle:

Provided further that if the pass is issued for more than one sealed road/ restricted road, a consolidated pass shall be issued on such form as may be specified by notification.

(4) Temporary passes for sealed and restricted roads for the purpose of shooting of films or for any commercial or entertainment purpose may be granted by the Secretary (Home) to the State Government for a maximum period of 7 days on payment of a fee of Rs. 3000 per day per vehicle upto a maximum of 10 vehicles:

Provided that in order to avoid danger or annoyance to pedestrians, conditions may be imposed while granting a pass, in relation to the hours of its validity and parking restrictions.

Enforcement
of provisions
of this Act.

10. In order to enforce the provisions of this Act, the Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police, Shimla shall ensure,—

- (a) Provision of signages at entry points and other conspicuous places on all sealed and restricted roads indicating the name of the road and the relevant provisions of this Act;
- (b) Deployment of sufficient traffic police specially at peak hours in order to enforce the provisions of this Act;
- (c) Placement of Barriers at strategic points on sealed roads to ensure that vehicles do not use such roads as thoroughfares or drive at high speed; and
- (d) On the spot checking, at frequent intervals, of the vehicles plying on the sealed/restricted roads, by an Executive Magistrate or Police Officer not below the rank of Inspector.

Penalty.

11. (1) Whoever contravenes any of the terms and conditions of the pass, shall be punished with a fine of Rs. 2000 or undergo simple imprisonment of one month in default thereof:

Provided that each such offence may be compounded by a Police Officer not below the rank of Inspector for a compounding fee of Rs. 1000.

(2) Subject to sub-section (1), whoever contravenes any of the provisions of this Act, shall be punished with a fine of Rs. 3000 or undergo simple imprisonment of one month, in default thereof:

Provided that an officer not below the rank of Sub-Inspector may compound the offence for a compounding fee of Rs. 1500.

(3) If any person fails to pay the compounding fee, the Registration Certificate of the vehicle shall be impounded alongwith the Driving License of such person and the case shall be forwarded to the Judicial Magistrate, having jurisdiction.

12. (1) If a pass holder is detected violating the terms and conditions of pass, in addition to any penalty provided under section 11, the pass may be cancelled by the Secretary (Home) to the State Government: Cancellation of passes.

Provided that no such order of cancellation shall be passed without affording a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police, Shimla, shall intimate any infringement of this Act, by a pass holder, which makes a pass liable for cancellation, on detection, to the Home Department.

(3) A person whose pass has been cancelled for violation of terms and conditions of the pass shall not be eligible for grant of any pass in his name or in the name of any family member for the same vehicle within one year from the date of the cancellation order.

13. (1) An appeal against the order of the Judicial Magistrate may Appeal. be made to the Sessions Judge having jurisdiction, within 30 days from the date of the said order.

(2) An appeal against cancellation of a pass may be made to the Additional Chief Secretary (Home) or the Principal Secretary (Home) to the State Government, as the case may be, within 15 days from the date of the cancellation order.

14. (1) With effect from such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established for the purposes of this Act, a fund to be called "the Shimla Road Users and Pedestrians Amenities Fund". Utilization of the proceeds of the fee and fines.

(2) The fund shall be used for the development of pedestrian amenities along sealed and restricted roads, improvement of pedestrian safety, development of convenient parking places with concessional rates for residents, access control and monitoring equipment etc., in order to regulate vehicular movement on sealed and restricted roads and reduce the likelihood of danger or annoyance to the pedestrians.

(3) A Committee headed by the Divisional Commissioner, Shimla and comprising of Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Deputy Commissioner, Shimla and Superintendent of Police Shimla, shall administer the fund.

(4) The Committee may—

- (i) make recommendations on inclusion / deletion of roads from sealed or / restricted roads;
- (ii) recommend sites for parking places;
- (iii) clear proposals for utilization of moneys credited in the fund and monitor progress;
- (iv) monitor the enforcement of this Act; and
- (v) carryout such other related activities as may be prescribed.

(5) Proceeds of the fees and fines deposited under this Act, shall be credited to the Consolidated Fund of the State and may be appropriated by law if the State Legislature so provides, to the fund in such manner as may be prescribed.

Power to
amend
Schedules.

15. The State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, add to or delete from Schedule-I or Schedule-II any of the roads specified therein and thereupon the said Schedules shall stand amended accordingly.

Powers to
relax.

16. The State Government may, in the public interest, relax any of the provisions of this Act, for any class of passes, for reasons to be recorded in writing, for a period not exceeding seven days at a time.

Bar of
jurisdiction.

17. No civil court shall have any jurisdiction or power to entertain or decide questions relating to matters falling under this Act.

Removal of
difficulties.

18. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

19. (1) The State Government may, by a notification, make rules consistent with this Act for carrying out the provisions of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before expiry of the sessions in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

20. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, the provisions of any other laws for the time being in force. Application of other laws not barred.

21. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith.

22. (1) The policy guidelines to regulate traffic on sealed and restricted roads issued *vide* Home Department endorsement number Home-C(E)-2-1/2000, dated the 20th December, 2003 and any other guidelines, notifications or orders issued in this behalf, from time to time, are hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the policy guidelines, notifications or orders so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Schedule-I

[See sections 2 and 3]

LIST OF SEALED ROADS

Road Code	Name of road
1	2
S-1.	From Chhota Shimla Chowk to Oakover.
S-2.	From Oakover to Chalet Day School.
S-3.	From Chalet Day School to Metropole Hotel.
S-4.	From lower bifurcation of Indira Gandhi Hospital to Lakkar Bazar.
S-5.	From Jodha Niwas to Ritz.
S-6.	All the connecting roads from the Mall Road leading to Ridge.
S-7.	From Hotel White to Regal Cinema/ Ridge.
S-8.	Kennedy House Chowk to Gorton Castle.
S-9.	Railway Board Building to Army Training Command .
S-10.	Link road from Tara Hall School Crossing towards Kalibari and upto Shimla Typewriter Company connecting The Mall Road.
S-11.	Scandal Point to Kalibari.

Note.—The roads extending from Central Telegraph Office (both upper and lower sides) via Mall Road to Ridge (in particular upto Ladies Park parking below Jodha Niwas on one side of the Church and route from Jakhu diverting towards Regal Cinema on the other side) and from Central Telegraph Office upto Shimla Club forming the Core Mall Road shall be banned to all the traffic except High Dignitaries and public utility vehicles and no passes shall be issued on the grounds of work or residence for such roads.

Schedule-II

[See sections 2 and 3]

LIST OF RESTRICTED ROADS

Road Code	Name of road
1	2
R-1.	From Kennedy House Chowk to Police Station Chowk to Peterhoff/AIR Station/IIAS.
R-2.	Peterhoff/All India Radio Station/Indian Institute of Advanced Studies to Boileauganj.
R-3.	From Cart Road to Deputy Commissioner Office.
R-4.	From Cart Road to Sabji Mandi.
R-5.	From Sanjauli Chowk to lower bifurcation Indira Gandhi Hospital (Lakkar Bazar).
R-6.	From Forest Lodge (Ramchandra Chowk) to Jodha Niwas <i>via</i> U.S. Club.
R-7.	From Cart Road to Gorton Castle.

Note.—The following roads are open for only light vehicles for which no permit is required:—

1. Link Road from Cart Road (Medical College side) to IGMH Hospital.
2. From St. Bedes College Chowk to Forest Lodge.
3. From Cart Road *via* Fire Sub-Station Chhota Shimla, Benmore to Oakover Chowk.
4. From Cart Road (near St. Edwards School) to Marina Hotel.
5. Cart Road-Annandale *via* Kennedy House Chowk.

